संख्या- 20 /2019/ 2297/अडतीस-7-2019-134/2015टीसी-2

प्रेषक,

विजय बहादुर वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 15 अक्टूबर, 2019**

विषय- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजनान्तर्गत द्वितीय चरण के 02 क्लस्टर्स की सीजीएफ की द्वितीय किश्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-06/1913/श्यामाप्र0मु0रू0मि0/2019-20 दिनांक 16-09-2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-12011/28/2015रूर्बन(एसएलनं0-17), दिनांक: 13-09-2019 द्वारा द्वितीय चरण के 02 क्लस्टर्स क्रमशः धौरहरा, जनपद वाराणसी हेतु रू0 540.00लाख(रूपये पांच करोड चालीस लाख मात्र) एवं कोदई, जनपद सोनभद्र हेतु रू0 270.00 लाख (रूपये दो करोड सत्तर लाख) की दर से केन्द्रांश की धनराशि रू0 810.00 लाख(रूपये आठ करोड दस लाख मात्र) तथा राज्यांश की धनराशि रू0 540.00 लाख (रूपये पांच करोड चालीस लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 1350.00 लाख (रूपये तेरह करोड पचास लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने हेतु निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. आंकडों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त,ग्राम्य विकास का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों/कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों/कार्यों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाने वाला व्यय अनुमन्य न होगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते मे रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज का नियमानुसार समायोजन/ निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग का होगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों तथा भारत सरकार के पत्र/स्वीकृत आदेश दिनांक 13-09-2019 की शर्तों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
8. धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक: 22 मार्च, 2019 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनान्तर्गत निर्धारित मद में वित्तीय नियमों के अनुपालन का दायित्व अपर आयुक्त(वित्त), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक "4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- 102- सामुदायिक विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशा0 पत्र संख्या-यूओ-ई-2-793 /X-19, दिनांक: 03 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या- 20/2019/ 2297(1)/अइतीस-7-2019 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार(रूर्बन डिवीजन), कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2. प्रमुख सचिव/निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
5. अपर आयुक्त (मनरेगा/वित्त), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मण्डलायुक्त, वाराणसी एवं मीरजापुर मण्डल, उत्तर प्रदेश।
8. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी एवं सोनभद्र, उ0प्र0।
9. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
11. राज्य योजना आयोग-1/2
12. विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग।
13. गार्ड बुक।

आज्ञा से

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।